



NaMo 25 · #25YearsofSewa

ANNADATA · किसान कल्याण

अन्नदाता — बीज से बाज़ार तक

मिट्टी की जाँच से लेकर सीधे खाते में सहायता और मंडी से ई-नाम तक — गुजरात के खेत से शुरू हुई कई योजनाएँ आज राष्ट्रीय हैं।

7 अक्टूबर 2001 → 7 अक्टूबर 2026 · 25 साल, ज़ीरो ब्रेक · modi25.in · संस्करण 52 · 5 अक्टूबर 2026
हर आँकड़ा तिथि सहित — पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर।



4.46 लाख करोड़+

रुपये पीएम-किसान से सीधे खातों में

24 फरवरी 2019 से 23 किस्ते; 23वीं किस्त 2.18 करोड़ महिला किसानों को भी मिली

3,765 लाख टन

अनाज का उत्पादन

2025-26 में — अब तक का रिकॉर्ड (तीसरा अग्रिम अनुमान)

1.4 लाख करोड़ ₹

रुपये — कृषि मंत्रालय का बजट 2026-27

₹1,40,529 करोड़ — 2013-14 के ₹21,933 करोड़ से लगभग छह गुना

1.8 करोड़+

किसान ऑनलाइन मंडी ई-नाम से जुड़े

2016 से; 1,656 मंडियाँ भी जुड़ीं

10,000

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

लक्ष्य फरवरी 2026 में पूरा — छोटे किसानों की सामूहिक ताकत

266.50 ₹/बैग

रुपये में यूरिया का बैग — किसान के लिए दाम स्थिर

45 किलो का बैग; बाकी लागत सरकार सब्सिडी से देती है

59,261

सहकारी समितियाँ (पैक्स) कंप्यूटर से जुड़ीं

दिसम्बर 2025 तक; लक्ष्य 79,630

1.98 करोड़ टन

मछली का उत्पादन 2024-25

2013-14 के 0.95 करोड़ टन से दोगुने से अधिक

2003-04

मिट्टी की जाँच के कार्ड की शुरुआत

गुजरात में शुरू हुए; 2015 में राष्ट्रीय योजना बने

पड़ाव — तिथिवार

2003-04 → 2015

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

2003-04 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू की गई योजना 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय योजना बनी, जिससे हर खेत की मिट्टी की रिपोर्ट किसान के हाथ में पहुँची।

13 जनवरी 2016

पीएम फसल बीमा

कम प्रीमियम पर फसल की सुरक्षा मिली, ताकि प्राकृतिक आपदा में किसान अकेला न रहे।

14 अप्रैल 2016

ई-नाम

राष्ट्रीय कृषि बाजार से मंडियाँ ऑनलाइन जुड़ीं; फरवरी 2026 तक 1.8 करोड़ से अधिक किसान और 1,656 मंडियाँ इससे जुड़ चुकी हैं।

2018

लागत का डेढ़ गुना एमएसपी

बजट 2018-19 से समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुने पर तय होता है।

24 फरवरी 2019

पीएम-किसान

हर वर्ष ₹6,000 सीधे खाते में पहुँचते हैं; 23 किस्तों में अब तक ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँचे।

2019

पीएम-कुसुम

खेत पर सौर पंप और सौर ऊर्जा से किसान बिजली का उत्पादक भी बना।



2020

10,000 किसान उत्पादक संगठन

छोटे किसानों को बाज़ार की सामूहिक ताक़त देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य फरवरी 2026 में पूरा हुआ।

2023

श्री अन्न — अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष

भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया।

नवम्बर 2024

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

रसायन-मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू हुआ; सिक्किम देश का पहला शत-प्रतिशत जैविक राज्य है।